प्रदेश के नौ शहरों के विस्तारीकरण के लिए विकास प्राधिकरणों को चार हजार करोड़ से अधिक के सीड कैपिटल की मिली मंजूरी

बांदा समेत नौ शहरों का चार हजार करोड़ से कायाकल्प

कैबिनेट फैसला

- कैबिनेट ने 24 में से 23 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फैसलों की जानकारी दी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार ने नौ विकास प्राधिकरणों को विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 4164.16 करोड़ रुपये देगी। इन प्राधिकरणों में सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ शामिल हैं।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सीड कैपिटल के रूप में 4164.16 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इसके तहत 1285 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इस योजना में भूमि अर्जन में आने वाले खर्च का प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने का प्रावधान है। नए शहरों का समग्र व समुचित विकास मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास होगा। साथ ही बढ़ती आबादी के मद्देनजर आवासीय सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी।

लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को 1680 करोड़

लखनऊ। लखनऊ के पीएम मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क निर्माण पर 1680 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह रकम मास्टर डवलपर खर्च करेगा। इस डवलपर के चयन के लिए कैबिनेट ने इससे संबंधित बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी दे दी। इस पार्क के निर्माण के बाद लगभग दस हजार करोड़ का निवेश होगा और सीधे तौर पर एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हथकरघा व वस्त्रोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि अब इस आधार पर जल्द डवलपर का चयन होगा। उसके द्वारा जो जमीन निवेशकों को बेची जाएगी। उसका कुछ हिस्सा यूपी सरकार को मिलेगा। जो कंपनी ज्यादा हिस्सा सरकार को देगी उसका चयन होगा। कंपनी कम से कम 1680 करोड़ रुपये पार्क के अंदर बुनियादी सुविधाओ पर खर्च करेगी।

एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जीएसटी से बाहर

वित्तमंत्री ने बताया कि सेंट्रल एक्ट में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी में संशोधन का फैसला मंत्री परिषद् द्वारा किया गया है। इसके तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से निकाल कर वैट में डाला गया है। इससे यूपी का राजस्व बढ़ेगा।

एटीएस, सुरक्षा विभाग के लिए 959 नए वाहन

लखनऊ। सुरक्षा विभाग और एटीएस के लिए पुलिस महकमे में 959 वाहनों को खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग के इन प्रस्तावों को कैबिनेट ने शुक्रवार को पास कर दिया है। इनमें वीवीआईपी और वीआईपी की फ्लीट के लिए 76 स्कार्पियों की खरीद की जाएगी। इसी तरह निष्प्रयोज्य वाहनों की जगह 899 नए वाहन खरीदने की मंजूरी मिल गई है। एटीएस में निष्प्रयोज्य 37 वाहनों के स्थान पर 37 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी पास कर लिया गया है। इसके अलावा 23 नए दोपहिया वाहन खरीदे जाएंगे। गृह विभाग ने यूपी पुलिस के सभी विभागों से इस बारे में प्रस्ताव लिए थे।

महाकुम्भ के लिए देश और विदेश में भव्य रोड शो होगा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार देश के बड़े नगरों व विदेश से श्रद्धालुओं को महाकुंभ में आने को प्रोत्साहित करने को रोड शो करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें महाकुम्भ 2025 के लिए देश के तमाम बड़े शहरों और विदेशों में भव्य रोड शो के आयोजन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया है।

इसके अलावा महाकुम्भ के लिए 220 वाहनों की खरीद का रास्ता भी साफ हो गया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में भव्य महाकुम्भ का आयोजित हो रहा है। सनातन धर्म के इस सबसे बड़े उत्सव को भव्य बनाने को लेकर योगी सरकार मिशन मोड में जुटी हुई है।

13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा महाकुम्भ

220 वाहनों की खरीद करेगी सरकार

मंत्री एके शर्मा ने बताया कि महाकुम्भ के लिए सरकार ने 220 वाहन खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए 27.48 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इनमें 40 महिन्द्रा बोलेरो नियो, 160 बोलेरो बी6 बीएसवीआई और 20 बसों की खरीद की जाएगी।